राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 5691/2012

हरदेव जाट पुत्र श्री उदय राम जाट, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी- ग्राम हरिपुरा, ग्राम पंचायत तस्वारिया, तहसील हुरदा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से राजस्थान राज्य और अन्य।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता (गण) के लिए	:	श्री मानवेंद्र सिंह राठौर की ओर से श्री प्रद्युम्न सिंह
उत्तरदाता(गण) के लिए	:	कोई उपस्थित नहीं है

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

<u>आदेश</u> (मौखिक)

<u>05/01/2024</u>

1. याचिकाकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ 13 मई, 2011 (अनुलग्नक-2) और 23 मार्च, 2012 (अनुलग्नक-11) के आक्षेपित आदेशों को रद्द करने के लिए 3,14,974/-रुपये की वसूली लगाने के साथ, एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की मांग करता है।

2. पहले स्पष्ट तथ्य।

2.1. याचिकाकर्ता ने फरवरी 2005 से जनवरी 2010 तक 5 साल की अवधि के लिए ग्राम पंचायत तस्वरिया के सरपंच के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान, याचिकाकर्ता ने मनरेगा योजना के तहत कई परियोजनाएं शुरू कीं, जिन्हें बिना किसी शिकायत के सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

2.2. हालाँकि, हरिपुरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने 24 जनवरी, 2011 को याचिकाकर्ता के खिलाफ अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। अधिकांश शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता के रिश्तेदार हैं, और उनके बीच एसडीओ के समक्ष एक दीवानी मुकदमा लंबित है। यहां तक कि याचिकाकर्ता के पक्ष में एक अंतरिम आदेश भी 29 दिसंबर, 2010 को राजस्व मुकदमा संख्या 402/2010 में पारित किया गया था।

2.3. एसडीओ गुलाबपुरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच के दौरान, कुछ अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया था, जिसमें बजरी वाली सड़क पर किए गए काम के मूल्यांकन में विसंगतियाँ और अन्य परियोजनाओं के संबंध में अन्य अप्रमाणित आरोप शामिल थे।

2.4. हरिपुरा की नहर, मधुसागर तालाब और हरिपुरा तालाब, भोचा का कुआ की नहर में किए गए काम के बारे में भी आरोप लगाए गए थे, जिसमें सीमेंट प्लास्टर और प्रतिलिपि बनाने के काम में अनियमितताएं शामिल थीं।

2.5. याचिकाकर्ता और अन्य लोगों के खिलाफ 1 अक्टूबर, 2011 को भीलवाड़ा जिले के पी. एस. गुलाबपुरा में भी एफ आई आर संख्या 246/2011 दर्ज की गई थी।

2.6. इस प्रकार प्रतिवादी ने संक्षेप में 13 मई, 2011 को आक्षेपित नोटिस जारी किया और सरपंच, ग्राम सेवक, एस. टी. ए. और जे. टी. ए. को वसूली की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। आरोप से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध के बावजूद, कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।

2.7. याचिकाकर्ता ने आर. टी. आई. अधिनियम के तहत दस्तावेजों की प्रतियों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए, लेकिन ये उपलब्ध नहीं कराए गए।

2.8. याचिकाकर्ता ने आरोपों को नकारते हुए और विसंगतियों के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करते हुए 24 अक्टूबर, 2011 को जवाब दायर किया। याचिकाकर्ता ने मनरेगा के तहत काम के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए परिपत्र मानदंडों का भी उल्लेख किया।

2.9. याचिकाकर्ता ने सुनवाई के अवसर के बारे में प्रतिवादी के साथ पत्राचार किया और काम के रिकॉर्ड प्रदान करने का भी अनुरोध किया लेकिन व्यर्थ रहा।

2.10. इसलिए यहां याचिका दायर की गई है।

3. प्रतिवादी के लिए कोई उपस्थित नहीं है।

4. दलीलें सुनी गईं।

5. 30 मई, 2012 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पर रोक लगा दी थी। अंतरिम सुरक्षा बनी हुई है।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को या तो वास्तविक दोषियों/अपराधियों को बचाने के लिए या उन शिकायतकर्ताओं को खुश करने के लिए बलि का बकरा बनाया गया है जिन्होंने अपने अन्य नागरिक विवादों के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रेरित शिकायत दर्ज की है, जैसा कि तथ्यों के पाठ में पिछले भाग में उल्लेख किया गया है।

7. इसके अलावा, रिकॉर्ड यह नहीं दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को कभी भी आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले नोटिस जारी करके सुनवाई या अन्यथा अपना बचाव करने का कोई अवसर दिया गया था।

8. अन्यथा भी, प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व न करना इस बात का संकेत है कि वे यहाँ आक्षेपित आदेशों का बचाव करने में रुचि नहीं रखते हैं।
9. इस आधार, इस न्यायालय द्वारा 30 मई, 2012 को पारित अंतरिम आदेश, जिसमें आक्षेपित आदेशों के संचालन पर रोक लगाई गई है, को पूर्ण बना दिया गया है।

10. तदनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। हालाँकि, आवेदन दायर करके कार्यवाही को पुनर्जीवित करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, यदि प्रतिवादी यहाँ आक्षेपित आदेशों का बचाव करने में रुचि रखते हैं और/या याचिकाकर्ता को लंबित आपराधिक कार्यवाही में दोषी ठहराया जाता है, जैसा भी मामला हो।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।